आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 12.07.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा।
- हरेला पर्व पर उत्तराखंड बनाएगा नया रिकॉर्ड, 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 5 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा– कॉमन सर्विस सेंटर, गांव–गांव में डिजिटल सेवाएं पहुंचाकर आमजन के जीवन को सरल बना रहे हैं।
- राज्य में अवैध और अपंजीकृत नशा मुक्ति केंद्रों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल बंद किया जाएगा।

विधानसभा मॉनसून सत्र

उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। यह सत्र 22 अगस्त तक चलेगा। सत्र आहूत किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले बजट सत्र 18 फरवरी से देहरादून में आयोजित किया गया था, जो पांच दिन चला था।

हरेला– वृहद पौधरोपण अभियान

इस वर्ष हरेला पर्व पर उत्तराखंड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 5 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। गढ़वाल मंडल में 3 लाख और कुमाऊं मंडल में 2 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा।

इस बार हरेला पर्व "हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ" और "एक पेड़ माँ के नाम" थीम पर मनाया जाएगा। अभियान के तहत पूरे जुलाई माह कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ग्रामीणों, स्कूली छात्रों और विभिन्न विभागों की सहभागिता, हरेला के सफल संचालन के लिये सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदेश में इससे पहले जुलाई 2016 में एक ही दिन में करीब 2 लाख पौधे रोपे गए थे, जिसका रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रकृति के बेहद करीब है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण सभी की जिम्मेदारी है। पौधरोपण सार्वजनिक स्थानों, वनों, नदियों, स्कूल–कॉलेजों, विभागीय परिसरों और आवासीय क्षेत्रों में किया जाएगा। इसमें जनप्रतिनिधियों, छात्रों, एनसीसी, एनएसएस और आम जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना–समीक्षा

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अधिकारियों ने योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति की जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि योजना के चौथे चरण के अंतर्गत दो हजार 645 गांवों को जोड़ते हुए नौ हजार 500 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में एक हजार 370 किलोमीटर की 212 सड़कों की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है और इन पर कार्य चल रहा है।

सड़क निर्माण की निगरानी के लिए ''इंस्पेक्ट टू परफेक्ट'' मोबाइल एप्प विकसित किया गया है, जिससे कार्यों की वास्तविक समय में निगरानी की जा रही है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखें और प्रगति में तेजी लाएं। उन्होंने पिथौरागढ़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों के उन गांवों को भी सड़क से जोड़ने के निर्देश दिए, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सड़क पहुंचना आवश्यक है।

प्रशासन सक्रियता–रुद्रप्रयाग

मानसून की सक्रियता और केदारनाथ यात्रा को देखते हुए रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना अनुमति मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन जरूरी है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रबंधन, यातायात, सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए प्रत्येक कार्यालय में न्यूनतम मानव संसाधन हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। कर्मचारी केवल विधिवत अवकाश स्वीकृत कराकर ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कार्यशाला

खसरा–रूबेला उन्मूलन अभियान 2025 के तहत चमोली के गोपेश्वर में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कार्यशाला का आयोजन में किया गया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी ने स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को गंभीरता से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि अभियान तीन चरणों में चलेगा, जिसका पहला चरण 21 से 31 जुलाई, तक होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जाएगा और बुखार व लाल चकत्तों जैसे लक्षण वाले मामलों की पहचान कर उपचार किया जाएगा।

सी०एस०सी दिवस– मुख्यमंत्री संबोधन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कॉमन सर्विस सेंटर–सी०एस०सी, आज गांव–गांव में डिजिटल सेवाएं पहुंचाकर आमजन के जीवन को सरल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 13 हजार से अधिक सीएससी संचालित हैं, जिनके माध्यम से यूसीसी पंजीकरण, प्रमाणपत्र और डिजिटल लेन–देन जैसे कार्य हो रहे हैं। वे देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम में आयोजित सीएससी दिवस–2025 कार्यक्रम में बोल रहे थे।

श्री धामी ने बताया कि राज्य सरकार ई–गवर्नेंस, ई–टूरिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी डेटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है।

नशा मुक्त उत्तराखंड

उत्तराखंड में नशा मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार अब अवैध और अपंजीकृत नशा मुक्ति केंद्रों पर सख्त कार्रवाई करने जा रही है। 'नशा मुक्त उत्तराखंड' अभियान को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों में निरीक्षण टीमें गठित करने और दोषी संस्थानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं।

राज्य सचिवालय में सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक में तय किया गया कि जिन केंद्रों का पंजीकरण नहीं है या जो निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें चिन्हित कर आर्थिक दंड और तत्काल बंदी की कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में किसी भी अपंजीकृत केंद्र को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में केवल वही संस्थान संचालित हो सकेंगे जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हों। उन्होंने आमजन से अपील की कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं, क्योंकि जागरूकता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बैठक में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और राज्य प्राधिकरण को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई।

निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने विभिन्न विभागों को जिलाधिकारियों के समन्वय से अपनी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग का कार्य सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही वन भूमि स्थानांतरण से जुड़े मामलों की हर माह समीक्षा बैठक करने को भी कहा है। देहरादून में विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक में श्री बर्धन ने जिलों में विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पूर्व में दिए गए लैंड बैंक निर्माण के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा। वन क्षेत्रों में क्षरित वन भूमि का विवरण देने और वन विभाग को भूमि हस्तांतरण मामलों के लिए एसओपी बनाने को भी कहा गया।

मुख्य सचिव ने जन शिकायत पोर्टल में समयबद्ध सेवाओं को शामिल करने, जिलों से दो सफल कार्यों की रिपोर्ट भेजने और सरकारी आयोजनों में स्थानीय उत्पादों के उपयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। हरेला पर्व पर व्यापक वृक्षारोपण के लिए सभी जिलों को तुरंत वृक्षारोपण योजना तैयार करने को कहा गया।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर....

पंचायत चुनाव में जिनका नाम दो मतदाता सूची में होगा वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यह ख़बर आज लगभग सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। अमर उजाला समाचार पत्र लिखता है जिनके नाम स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों जगहों की मतदाता सूचियों में दर्ज है, ऐसे प्रत्याशी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते।

ऑपरेशन सिंदूर मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान को दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला सहित लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया है। दैनिक जागरण श्री डोभाल के हवाले से लिखता है– ऐसा एक फोटो दिखाएं जिसमें भारत का नुकसान नजर आए। समाचार पत्र के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मीडिया को एन.एस.ए ने पाकिस्तानी हमले से भारतीय बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का सबूत पेश करने की चुनौती दी है।

बिना लाइसेंस इलाज करने वाले डॉक्टर के खिलाफ चलेगा अभियान, हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है। समाचार पत्र लिखता है– स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने डीजी हेल्थ के साथ ही सभी सीएमओ को सभी जिलों में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं।

ऑपरेशन कालनेमि के पहले दिन ढोंगियों पर हनुमान की तरह टूट पड़ी दून पुलिस। इस शीर्षक के साथ दैनिक जागरण की ख़बर है– मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के क्रम में पुलिस ने जिले में व्यापक रूप से चलाया अभियान।